



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR
BUY NOW

testbook

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2018 - GK नोट्स का PDF डाउनलोड करें!

एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "गरीबी कोई दैवीय अभिशाप नहीं है बल्कि यह मानवजाति द्वारा रचित सबसे बड़ी समस्या है"। विश्व में सुरसा की तरह मुँह फैलाती हुई गरीबी के निवारण और उन्मूलन के लिए हर साल पूरी दुनिया में **अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस** मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (आईडीईपी) हर साल गरीबी को खत्म करने के उपायों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2018 के लिए आईडीईपी का विषय है 'आंसरिंग द कॉल ऑफ अक्टूबर 17 तो इंड पॉवर्टी: अ पाठ टुवर्ड पीसफुल एंड इंकलूसिव सोसाइटीज'। यह विषय पूरी दुनिया से गरीबी खत्म करने के लिए सभी पृष्ठभूमि से गरीबी में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के महत्व पर जोर देता है। इस लेख को बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं के लिए इस विशेष दिन के बारे में जानने के लिए पढ़ें और आईबीपीएस पीओ, रेलवे समूह डी, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस क्लर्क इत्यादि जैसी आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें।

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस - पिछली थीम्स

2017 - आंसरिंग द कॉल ऑफ अक्टूबर 17 तो इंड पॉवर्टी: अ पाठ टुवर्ड पीसफुल एंड इंकलूसिव सोसाइटीज

2016 - मूविंग फॉर्म हुमिलिएशन एंड एक्सक्लूशन तो पार्टिसिपेशन: एंडिंग पावर्टी इन आल इट्स फॉर्म्स

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का इतिहास

पहली बार, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस साल 1987 में फ्रांस में मनाया गया था। जिसमें लगभग एक लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन एटीडी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसफ त्रेन्सिकी द्वारा आरंभ किया गया था। त्रेन्सिकी की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 दिसम्बर 1992 को प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस वर्ष का समारोह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की 25 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।





testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹400 FOR
4 MONTHS

testbook

BUY NOW

गरीबी उन्मूलन पर भारत की पहल

योजनायें	उद्देश्य
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मजदूरी रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी एनओएपीएस का उद्देश्य वृद्धावस्था में कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना है जिनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा है। उम्र 60-79 आयु वर्ग के लिए राशि 200 रुपये तय की गई है और 80 वर्ष से ऊपर के आवेदक के लिए राशि 500 रुपये तय की गई है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना अगस्त 1995 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30,000 / रुपये का भुगतान करेगी। पहले मुआवजे की राशि 20,000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है। जो परिवार इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में उल्लेख राशि का दावा/ आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना के तहत तीन किस्तों में एक गर्भवती मां (केवल 19 वर्ष से ऊपर है) को 6000 की राशि प्रदान करती है। हर संस्थागत जन्म के लिए इसे 1400 रुपये के साथ जननी सुरक्षा योजना के रूप में बदल दिया गया है।
अन्नपूर्णा	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना 1999 -2000 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक महीने के लिए मुफ्त 10 किलो अनाज प्रदान करना है। यह केवल उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो NOAPS के लाभों का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

LIVE COURSE

GA & BANKING AWARENESS

Banking Awareness
Financial Awareness
Important Current Affairs

**HURRY!!
500 SEATS ONLY!!**

BOOK NOW



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR

BUY NOW

testbook

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)	<ul style="list-style-type: none"> योजना 1978 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के टिकाऊ अवसर प्रदान करके पूरे देश से गरीबी उन्मूलन करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता प्राप्त लाभार्थियों का कवरेज 50% एससी और एसटी, 40% महिला लाभार्थियों व 3% विकलांग लोगों के लिए होना चाहिए।
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीए)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना 1985 में शुरू हुई थी। यह सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने और 20 लाख आवास बनाने के उद्देश्य से शुरू हुयी जिसमें से 13 लाख आवासों का निर्माण ग्रामीण इलाकों में होंगे। बैंकिंग संस्थान लोगों को अपने घर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर गृह ऋण देता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए)	<ul style="list-style-type: none"> यह योजना 2006 में लागू हुई थी और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) रखा गया था। यह ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को 150 दिनों का भुगतान कार्य प्रदान करता है।

हमें आशा है कि आपको यह लेख अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर आगामी परीक्षाओं के लिए मदद मिलेगी। अपने सामान्य ज्ञान को और बढ़ने के लिए ऐसों ही अन्य लेखों पर नज़र डालें।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा	भारतीय हवाई अड्डे और शहर
आधार अधिनियम संवैधानिक	भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और विजेता	बैंक विलय (बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक)

जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभ्यास सफलता की कुंजी है। इसलिए, अब अपना अभ्यास शुरू करके अपनी तैयारी को बढ़ावा दें।

[Solve Practice Questions for Free](#)

इसके अलावा, टेस्टबुक पर अपने संदेहों को हल करने के लिए अपने साथी उम्मीदवारों और हमारे विशेषज्ञों से बात करें:

[Go to Testbook Discuss](#)

